

प्रेषक,

संख्या: 34 भूक्य/18(1)/2006

एनोएसोनपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।  
सेवामें  
जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक २५ मई, 2006

विषय:—मैं ० कैलिक्स हर्बल लि० को फार्मसियूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रुडकी के ग्राम नल्हेडा अनन्तपुर में कुल ०.०९३७ हेक्टर भूमि क्य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—५७१/भूमि व्यवस्था—भूमि क्य दिनांक १९ अप्रैल, २००६ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मैं० कैलिक्स हर्बल लि० को फार्मसियूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (सशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक १५-१-२००४ की धारा—१५४(४)(३)(क)(v) के अन्तर्गत तहसील रुडकी के ग्राम नल्हेडा अनन्तपुर में कुल ०.०९३७ हेक्टर भूमि क्य करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं—

१— केता धारा—१२९-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अहं होगा।

२— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—१२९ के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों रो प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

३— केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान

11

.....(2)

की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे रवीकृत किया गया था, उरारो गिन किरी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा गिरा प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे गिन प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूखामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुरूपित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूखामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6— स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार/रोवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

7— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबधों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत रवीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०नपलच्याल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— मुख्य राजरव आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3— रायिय, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4— श्री बिलाल खौ, डायरेक्टर, गै० कैलिक्स हर्वल लिं० ग्राम रांसारपुर पगड़ा।
- 5— मुजफ्फरनगर, तसहील बेहट जिला सहारनपुर।
- 6— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तरांचल सचिवालय।
- 7— गार्ड काईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)  
अपर सचिव।